15.08 hrs.

SUGARCANE PRICE (FIXATION) BILL*

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): I beg to move for leave to introduce a Bill to fix the price of sugarcane.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to fix the price of sugarcane."

The motion was adopted.

SHRI P. RAJGOPAL NAIDU: I introduce the Bill.

15.8½ hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Omission of article 310, etc.)

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI BHAGAT RAM: I introduce the Bill.

15.10 hrs.

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE BILL

BY SHRI LAKKAPPA—*Contd.*

MR CHAIRMAN: We now take up further consideration of the following motion moved by Shri K. Lakkappa on the 10th March, 1978, namely:—

"That the Bill to provide for compulsory payment of allowance to all unemployed persons in the country be taken into consideration."

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, श्री लक्कप्पा ने जो यह विधेयक उपस्थित किया है, उस का मैं सिद्धान्त रूप से स्वागत करता हूं लेकिन जैसा मैं ने एक रचनात्मक संशोधन उपस्थित किया है, उस के अनुसार इस में थोड़ा जोड़ना चाहता हूं।

लक्कप्पा साहब के अनुसार बेरोजगारी केवल शिक्षित लोगों में ही है। इस से बढ़ कर कोई बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। जितने शिक्षित बरोजगार हैं उन से कई गुना ज्यादा अशिक्षित बरोजगार है। इसलिए उन का ध्यान उस तरफ़ दिलाने के लिए मैं ने यह संशोधन दिया है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : बिल से सब के लिए है एजूकेटेड और अनएजूकेटड।

डा० राम जी सिंह : हमारे माननीय साठ साहब ने मूल विधेयक का अध्ययन नहीं किया है। अगर वे धारा 2 को देख तो पाएंगे ;

"Every educated person including doctors, engineers...."

तो मैं यह कह रहा था कि बरोजगारी की समस्या केवल शिक्षित लोगों की ही नहीं होती हैं बल्कि अशिक्षित लोगों की भी है और बरोजगारी का सवाल केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं है बल्कि वह एक ग्लोबल फनोमेनन है और साम्यवादी देशों को छोड़ कर ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर यह सवाल न हो, यहां तक कि विकसित देशों जैसे अमेरिका और इंगलैंड जैसे देशों में बरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर समय रहता तो मैं आप के सामने आंकड़ देता कि किस तरह से अमेरिका और इंगलैंड जैसे विकसित और उन्नत देशों में प्रति वर्ष बेकारी का प्रश्न बढ़ता ही जा रहा है लेकिन भारतवर्ष की

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 23-3-78.

समस्या सब से ज्यादा है। भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति गिरि साहब ने "जोब फार दि मिलियन" नामक जो पुस्तक लिखी है, उस मे जो बेकारी के आंकड दिये हैं वे करीब 13 करोड़ के हैं। यह 30 वर्षों की कमाई है हिन्दुस्तान मे। प्रश्न यह है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। यह निश्चित बात है कि पार्टी के आधार पर इस समस्या का समाधान नही किया जा सकता है यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसमे सब लोगो को मिलजुल कर लगना होगा। वस्तुत यह जो बेकारी का प्रश्न है, इस मे हमे यह देखना पडेगा कि हमारी योजना की दिशा ही गलत थी और यही कारण है कि बकारी दिन प्रति दिन बढती गई। प्रथम पचवर्षीय योजना पूरी हुई तो केवल पौन करोड लोग बेकार थ, दूसरी योजना पूरी हुई तो सवा करोड बकार थे, तीसरी योजना मे यह सख्या पौने दो करोड हो गई और पचम पचवर्षीय योजना और 20 सूत्री और 25 सूत्री कार्यक्रम आया, तो उसके बाद देश मे 13 करोड आदमी बकार हो गय है। इस से यह प्रमाणित होता है कि योजना की जो दिशा थी, वह निश्चित रूप से गलत थी और बकारी पैदा करने वाली थी। इसलिए मैं यह सोचता ह कि बेकारी को दूर करने के लिए जो पहला प्रश्न है, वह यह है कि हमारी योजना रोजगारमुखी होनी चाहिए, एम्पलायमेंट आरियेन्टेड" होनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि हमारी बाजना रोजगारमुखी नही रही है लेकिन प्लानिग से ही केवल बेरोजगारी की समस्या का दूर नही कर सकते हैं। अच्छा यह होगा कि हमारा "डवलपमेंट ओरियन्टेड एम्पलायमेंट" हो और उस रोजगार से विकास मे सहायता मिले। केवल 50, 50 रुपये की भीख दे कर हिन्दुस्तान मे भीखमगो की जमात खडी करने से न तो देश का विकास होगा और न रोजगार की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए अभी भी जब हम किसी रोजगार की नीति को निर्धारित करें, तो हमे देखना होगा कि उस से राष्ट्र का विकास होता है या नही। केवल इतने से ही काम नही चलेगा बल्कि दूसरी बात यह भी देखनी चाहिए कि रोजगार के सवाल को शिक्षा से जोड़ना होगा। इसलिए हमारी "एम्पलायमेंट आरियन्टड एजूकेशन" हो। पिछले 50 वर्षों से जो शिक्षा की दिशा हमे मैकाले साहब से विरासत से मिली है, उस को ही हम 30 वर्षों से ढोते रहे है। यही कारण है कि आज देश मे इतने लोग बेकार हैं। जब तक शिक्षा मे आमूल परिवर्तन नही होगा, जैसा गाधी जी ने कहा था कि शिक्षा को योजना से जोडा जाए यह नही किया जायगा, तब तक समस्या हल नही होगी। वर्तमान शिक्षा मे केवल बरोजगार पैदा करने की क्षमता है। जब इजीनियर और डाक्टर बेकार रहते है तब उनकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता है लेकिन भारत मे जो करोडो लोग और बेकार है उनकी तरफ नही जाता है। हिन्दुस्तान मे बरोजगारी की जो समस्या है उससे भी ज्यादा विकट, ज्यादा गम्भीर समस्या अर्ध बकारी की है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहा कृषि मे लगे हुए लोगो को साल भर काम नही मिलता है। साल मे छ या चार महीने ही काम मिलता है। देश मे पाच लाख गाव है। सभी गावो मे अर्ध बेकारी की समस्या व्याप्त है। उनके लिए क्या हो सकता है। उनके लिए आवश्यक है कि कृषि का विकास किया जाए। उसके बिना गावो मे रहने वाले जो रूरल पूअर है उनका विकास नही हो सकता है। अगर इस समस्या को दूर करना है तो कृषि का विकास और उसके साथ-साथ ग्रामोद्योगो का विकास करना होगा। गावो मे रहने वालो का आप राउरकेला भिलाई, बोकारो जैसे प्लाट बना कर रोजगार नही दे सकते है। हमारी अपनी सीमाय है। हमारे पास ज्यादा पूजी नही है। बड कारखानो म जहा एक आदमी को रोजगार देने म पाच लाख रुपया लगता है वहा छोटा रोजगार देने मे लघु उद्योग स्थापित करने मे और उस मे उनको रोजगार देने मे केवल पाच रुपये की पूजी लगती है। इसीलिए

[श्री रामजी सिंह]

इंग्लैंड के बड़े अर्थशास्त्री शूमाखर ने कहा है कि "स्माल इज ब्यूटीफुल" । हिन्दुस्तान जैसे विकासशील देश में बड़े उद्योगों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । जो बड़े उद्योग आवश्यक हैं वे तो लगने चाहिये । लेकिन जहां उनकी आवश्यकता नहीं है, नहीं लगने चाहिए । अगर बेरोजगारी को देश से दूर करना है तो निश्चित रूप से कृषि का विकास करना होगा और उसके साथ साथ ग्रामोद्योगों का विकास करना होगा ।

इस समस्या का हल सुझाने के लिए भगवती कमेटी ने काफी सुझाव दिए हैं । मैं उन की पुनरावृत्ति करके इस महान सदन का समय अपव्यय नहीं करना चाहता । लेकिन इसके सिलसिले में जो प्रस्ताव लकप्पा साहब ने एक बड़े सुन्दर हृदय से लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए रखा है कि एलाउंस दिया जाए उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक बात है कि कुछ राज्यों ने एलाउंस दिया है, भारत में सब से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार बंगाल में है और वहां की सरकार ने एलाउंस उनको दिया है, इसका मैं विरोध नहीं करता हूं लेकिन प्रश्न यह है कि केवल कुछ लोगों को दस बीस या पचास रुपये दे देने से समस्या हल हो जाएगी ? जब योजना आयोग के सामने यह समस्या आएगी तो उसको सोचना होगा कि इसको कैसे हल करना चाहिए । सचमुच में जनता पार्टी के घोषणापत्र में हम लोगों ने वायदा किया है कि सभी को हम रोजगार देंगे । लेकिन क्या एक वर्ष में रोजगार दिया जा सकता है ? सचमुच में इसके लिए दस वर्ष का कार्यक्रम घोषित किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह कार्यक्रम और यह वाणी खोखली साबित हुई तो जनता पार्टी का भी वही हाल होगा जो हमारे विरोधी मित्रों का हुआ है । इसलिए आवश्यक है कि दस वर्ष की इस योजना को साकार किया जाए इसको मूर्त रूप दिया जाए और हम सब लोगों को सरकार से आग्रह करना चाहिए कि कालबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, एक वर्ष में कितने दो वर्ष में कितने लोगों को रोजगार, काम देना चाहिये और इस तरह से इस समस्या को हल करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि "राइट टू वर्क" अभी संविधान में शामिल कर दिया जाए । मैंने विधेयक भी उपस्थित किया है इसके सम्बन्ध में अगर आप संविधान में संशोधन कर देते हैं कि हर आदमी को रोजगार दिया जाए और यह उसका अधिकार है तो भारत का योजना आयोग जो है उससे अगर आप जा कर पूछें कि वह क्या एका एक ऐसा कर सकेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज वह विफल और असफल होगा । इसलिए "राइट टू वर्क" सिद्धान्ततः ठीक है लेकिन उसको दस वर्ष में बांध देना चाहिये ।

लकप्पा साहब ने कहा है कि जितने बेरोजगार हैं उनको एलाउंस दिया जाए । कितनों को देंगे ? हिन्दुस्तान में बेकारों की संख्या चार, पांच हजार या लाख में तो है नहीं, 30 सालों के शासन के कारण आज 13 करोड़ लोग बेकार हैं । वह कहते हैं कि 15 करोड़ रु० लगेगा । तो माननीय लकप्पा के गणित और अंकगणित की परिभाषा दूसरी होगी, मेरे विचार से इसके लिये 40 अरब रुपये लगेंगे, जो हिन्दुस्तान की आर्थिक योजना की शक्ति के बाहर की बात है । इसलिये ऐसी बात करनी चाहिये जो अच्छी हो और व्यावहारिक हो । और जैसे तैसे देने से क्या होगा कि भिखमंगी की प्रवृत्ति बढ़ेगी । इसलिये मैं माननीय लकप्पा की भावना का आदर करता हूं और अपनी सरकार से, खुशनसीबी है कि श्रम मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वह सचमुच में ऐसा रोजगार दें जिससे श्रम की प्रतिष्ठा बढ़े । भीख में रुपया लेने वाले का तो अपमान है ही, देने वाले का भी अपमान है ।

इसलिये आप लोगों को भीख स्वरूप न दीजिये, बल्कि काम दीजिये और देते जाइये प्रति वर्ष तभी जनता पार्टी और राष्ट्र का सम्मान बढेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय लकप्पा की भावना का आदर करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरा जो निर्दोष संशोधन है उसको स्वीकार कर लें । और जैसा मैंने कहा है :

"The Government, keeping in view the financial resources, will execute the Unemployment Allowance Scheme in phase starting with the Scheduled Caste and Scheduled Tribes and Backward Classes."

जो समाज का सबसे अन्तिम व्यक्ति हैं वहीं से करना चाहिये । इसीलिये जो भी हम काम करें, चाहे काम देने का हो, तो समाज का जो अन्तिम व्यक्ति है वहीं से हम अपना कार्य करना चाहिये ।

श्री लखन लाल कपूर (पूर्णिया) : सभापति महोदय, मुझे एक विधेयक पेश करना था ।

सभापति महोदय : अच्छी बात है, इनको इंट्रोडयूस कर लेने दीजिये बिल ।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर साढ़े तीन बजे बहस होनी थी, पहले मेरा नाम था और मैं बैठा रहा, और आपने हमारा नाम समय से पहले बुला दिया ।

सभापति महोदय : आपकी व्यवस्था का प्रश्न मैंने सुन लिया । सदन से हमने पूछा था, आफ़िशियल बिजनेस समाप्त हो गया था । तो या तो सदन 24 मिनट के लिये ऐडजर्न कर के फिर दुबारा मिलते, या सदन का काम चालू रखते समय ऐडवांस कर के प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस का । हाउस ने एक मत से निर्णय दिया कि प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस को ऐडवांस कर दिया जाय । हमने कर दिया । आप बाद में आये । आपको भी बुला लिया जायगा, उसमें कोई दिकक्त की बात नही है । आपको तकलीफ़ न हो उसके लिये व्यवस्था की है । जो अपने बिल इंट्रोडयूस नही कर सके उनको बीच में इंरप्ट कर इजाजत दी जा रही है । कोई परेशानी की के बात नही है ।

15.22 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Articles 330 and 332)

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

The motion was adopted.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित भी करता हूं ।

15.23 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Seventh Schedule)

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2 dated 23-3-78.